(ग) जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने, वहां शांति बहाल करने तथा राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने में सरकार को कितनी सफलता मिली है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) सरकार को उन सिविलियनों की जान व माल के लिए उत्पन्न खतरे की जानकारी है जिनके बारे में आतंकवादी यह समझते हैं कि वे उनके साथ सहयोग नहीं करते तथा उनमें वे सिविलियन भी शामिल हैं जिन्हें उन्होंने "मुखबिरों" की संज्ञा दी हुई है। सरकार का प्रयास एक ऐसा माहौल तैयार करने का है जिसमें राज्य के सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सकें।

आतंकवादियों पर लगातार दबाव बनाए रखा गया है, उन्हें बाहर खदेड़ने और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए चलाए गए अभियानों को पुरजोर ढंग से जारी रखा गया है और अस्पतालों सहित संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। यद्यपि, आतंकवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा और बन्दूक का भय बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए हैं, फिर भी आतंकवादियों के प्रति जनता के रवैये सहित स्थिति में बदलाव आया है तथा आतंकवादियों के हौसलों में कमी आई है तथा उनमें अव्यवस्था फैली हुई है।

सरकार का विचार आतंकवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए रखने का है तथा इनके साथ-साथ सामान्य स्थिति बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों और राजनैतिक प्रक्रिया को पुनः सक्रिय करने को बढ़ावा देने, जनता की भागीदारी के द्वारा विकास के कार्यों को तेज करने और स्थानीय प्रशासन को पुनः मजबूत बनाने के प्रयास जारी रखना है।

1995 में विधान सभाओं के चुनाव

*222. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995 में किन-किन राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव होने हैं ;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग ने इसके लिए फोटो पहचान-पत्र की शर्त रखी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य संचालय में राज्य मंत्री (श्री इंदरराज शरवाज) : (क) मणिपुर, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में और जम्मू-कश्मीर राज्य में भी, जहां राष्ट्रपति शासन के विस्तार किए जाने की वर्तमान अवधि 3-3-1995 तक विधिमान्य है, नई विधान सभाएं गठित किए जाने के लिए साधारण निर्वाचन वर्ष 1995 में होने हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकारें, फोटो पहचान-पत्र जारी करने के लिए सिद्धांत रूप से, सहमत हो गई हैं और उन्होंने वित्तीय और व्यावहारिक कठिनाइयों के रहते हुए भी, निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है। केन्द्रीय सरकार फोटो पहचान पत्रों के जारी किए जाने पर राज्यों द्वारा उपगत किए जाने वाले कुल व्यय के 50% की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत है।

Decontrol of Industries using Agricultural Produce as Raw Material

223. SHRI BHUPINDER SINGH MANN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the industries which use agricultural produce as their raw materials or their produce being used as input in agriculture are yet to be decontrolled;

(b) the reasons for keeping them under control, alongwith the details of such controls; and

(c) by when these are expected to be decontrolled ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI)

(a) and (b) : Industries based on agriculture for supply of raw materials still under licensing includes sugar, cigars, cigarettes and alcoholic drinks. The industries who

final product is being used as an input in agriculture and which are still under licensing relate to manufacture of certain hazardous chemicals like Phosgene and its derivatives used for making pesticides/insecticides. These industries have been kept under licensing for reasons relating to social considerations, environmental concerns and control on use of hazardous chemicals.

(c) The list of industries under compulsory licensing is reviewed from time to time.

अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं द्वारा विमानों की और अधिक उड़ानें भरने की अनुमति देने की मांग

***224. श्रीमति चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :**
श्री कृष्ण कुमार बिरला :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं एअर इंडिया के विमानों को अपने देश में अधिक गन्तव्य स्थलों और प्रवेश मार्गों की अनुमति दिये बिना ही भारत सरकार से भारत में ऐसी रियायतों की मांग पर जोर दे रही हैं;

(ख) क्या कुछ अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं विमानन प्राधिकारियों से और अधिक उड़ानों के प्रचालन की अनुमति देने की मांग कर रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार ने भी उपरोक्त अनुमति के बदले में ऐसी ही अनुमति देने की मांग की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर विदेशी विमानन प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) यातायात संबंधी मांग और अवसर तथा पारस्परिकता को ध्यान में रखते हुए, द्विपक्षीय आधार पर संबंधित सरकारों के अधिकारों के आदान-प्रदान की बाबत समझौता-वार्ता की जाती है ।

Technology Parks in India

*225. SHRI T. VENKATRAM REDDY :
SHRI GOVINDRAO ADIK:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) Whether Government have studied the scheme of Technology Parks which has been successful in Australia ;

(b) If so, whether Government intend to implement any similar scheme in India; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN PRIME MINISTER'S OFFICE AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY SPACE AND IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI) : (a) to (c) The Department of Science and Technology, after examining various models from abroad and in India, launched a scheme for setting up of Science and Technology Enterpreneur's Parks (STEPs) in the country, So far, the Department of Science and Technology has approved 12 STEPs in the country. The STEPs are jointly supported by the Department of Science and Technology, the all-India Financial Institutions, State Government and the host institution. STEPs provide infrastructural and technical support for innovation and entrepreneurship development.

In addition, Software Technology Parks (STPs) and Electronics-Hardware Technology Parks (EHTPs) schemes are being implemented under the aegis of the Department of Electronics.

Revival of closed sick fertilizer units to overcome Urea shortage

*226. DR. NAUNIHAL SINGH : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering to revive closed units of sick fertilizers PSUs in order to overcome the current urea shortage; if so, the details of the proposal;